*Postal Regd. MP/BHOPAL/244/18-20* *'ANASUYA' RNI-Regd. No. 45134/86*

प्रति अंक मूल्य - 4/-रु.
वार्षिक चन्दा 100/- रु. मात्र
आजीवन सदस्यता शुल्क : 700/-
1-16 मई 2020-संयुक्तांक

# अवैश्विकरण : खाद्य उद्योग का

इला र. भट्ट

आज विश्व के खाद्य उद्योग का सिस्टम ऐसा अटपटा और उलझन भरा बन गया है कि उसे समझने जाओ तो अनेकों गंभीर प्रश्न उठ खड़े होते हैं।

पोषक खुराक की सुरक्षा तो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है तो लाखों-करोड़ों लोग आज भुखमरी की स्थिति में क्यों हैं? जो अनाज उगाता है वही किसान खुद और खेत मजदूर क्यों आज भूखे हैं या आधापेट भोजन पर जी रहे हैं? जो देश खाद्य पदार्थों का निर्यात करते हैं वो देश भुखमरी में क्यों जीते हैं?

जब दुनिया के वार्षिक निर्यात के अहवाल में खेत की पैदावार शिखर पर हो तब उसी देश में किसान और खेत मजूदरों की गरीबी का स्तर इतना नीचे क्यों देखने को मिलता है? दुनिया की कुल श्रमशक्ति का आधा हिस्सा अन्न उत्पादन के क्षेत्र में लगा हुआ है तब भी उनके जीवन की स्थिति इतनी दरिद्र ही क्यों रही है? इसका कारण क्या है?

खाद्य उद्योग की व्यवस्था के मूल में ही खोट है, जिससे हम उस ध्येय को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस विश्व में कोई भूखा ना सोये। मुझे जवाब 'लोकल' में मिलता है, 'वैश्विकरण' में नहीं। यही तो जोखिम है।

मेरा मुद्दा है कि थाली पर बैठकर खाऊँ, ऐसी स्थानीयता हो। घर-रसोई, परिवार, मानसिक संतोष का खानगी अनुभव। खुराक के अनेकानेक पक्ष हैं।

वैश्विक प्राकृतिक वातावरण से लेकर अपनी आजीविका की कमाई तक अनेक प्रकार की परंपरा, श्रद्धा, विधि-पूजा, भक्ति, दंतकथा (myth 'मीथ') तक अन्न का प्रभाव है।

अन्न, खुराक, भोजन के साथ हमारे जीवन का संस्कार है। इसीलिए ही, भोजन करने की नित्यक्रिया को हम सरकारी भाषा में 'फूड सिक्योरिटी' करके, सिकोड़कर उसे अधिक पेचीदा

अनसूया

आद्य-संपादक : ज्योत्स्ना मिलन
संपादक : प्रीति शान्त

वर्ष : 35 अंक :13-14 मई 2020

कोविड-19 पर केंद्रित

भीतर

3. पश्चिम बंगाल का दृश्य ...
5. घरखाता कामगारों के लिए माँगपत्र ...
6. हर जरूरतमंद तक मदद पहुँचाई ...
8. सामान्य जीवन कब पटरी पर आएगा ...

न बनाएँ। ये तो सरकारी सोच है। हम तो अन्नपूर्ण को सदापूर्ण बनाते हैं, भोजन को उत्तम बनाते हैं, ना कि उसे नए बिजनेस-व्यापार बनाकर या व्यापार के अवसर झपटने की एक आर्थिक प्रवृत्ति। परंतु दु:खद तो यह है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था की राजनीति बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ नैतिकता का पतन होता जा रहा है।

खेती, ये तो मानव संस्कृति की नींव है। मूल प्रभवस्थान है और इस मूल पर ही अभी घातक प्रहार हो रहे हैं। दुनिया के देशों में, खासकर हमारे भारत में खेती का जीवन ही संकट में है। जो परिवारों की आत्मनिर्भरता पर ज़ोरदार थप्पड़ है। देखो तो, अपनी खेती, उपज, रीति, साधन, प्रकृति कैसे धीरे-धीरे विलीन होते गये हैं और अब तो तेजी से नष्ट हो रहे हैं।

तो, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने कृषि समाज का जीवन और जीविका को बचाना होगा। अपने खेती उद्योग की नींव को मजबूत करें। छोटे किसान बहन-भाईयों, उनके उत्पादन, उनके स्थानीय कृषि क्षेत्रों को संरक्षित करना होगा।

हमें अपने कृषि उत्पादों को, खेत की पैदावार को सम्हालना होगा। यह कोई नई बात तो नहीं, फिर उसका पालन करने में हम निष्फल क्यों हुए हैं? गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहनों को खासतौर पर विचार करना चाहिए क्योंकि उनके भीतर सपोषण की भावना अभी टिकी हुई है।

'जन जन स्वराज भोगे' इस मार्ग पर, खेती उद्योग को आधुनिक संदर्भ में विकसित करना होगा। सबको स्थानीय स्तर पर पर्याप्त और सस्ता अनाज प्राप्त हो। यह सबसे बड़ी चुनौती है।

अगर खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी जन-जन तक पहुँचानी हो तो सबसे पहले, सरकार सहित हमें समझना होगा कि ऐसी 'सिक्योरिटी' को स्वायत्तता की ज़रूरत है। तभी खाद्य की स्थानीयता और उसके फलस्वरूप अन्य खाद्य उत्पादों की विविधता पनपेगी।

स्वायत्तता, विविधता, स्थानीयता ये तीनों फूड सिस्टम के मुख्य स्तंभ हैं।

मेरा यह आग्रह है कि आज की दुनिया के फूड सिस्टम का अवैश्विकरण होना चाहिए। फूड सिस्टम के स्थानीयता के दायरे को विकसित करने का मौका मिलेगा तभी इस भूमि पर कोई भूख से नहीं मरेगा। अवश्य, यह कोई नई बात तो नहीं है।

*एक परिषद में, अफ्रीका के देश (घाना) की दो किसान मंच पर अपने देश की खेती की परिस्थितियों का अहवाल देते हुए जो बोलीं वो शब्द आज भी मेरे दिमाग में घुमते हैं। उन्होंने कहा,*

*'हम जो उगाते हैं वो हम खाते नहीं, और जो हम खाते हैं, वो उगाते नहीं।'*

*मैंने पूछा, 'आप क्या खाते हो?'*

*वे बोलीं, 'चिकन के साथ टोमेटो की प्यूरी, हमारी जमीन पर टमाटर उगाते, घर में उसको पकाकर रसेदार प्यूरी बनाते। हमने अपनी जमीन के एक कोने में मुर्गी पालने का एक बड़ा बाड़ा बना रखा है।'*

*'अभी क्या खाते हो?'*

*'यही। मार्केट का फ्रोज़न चिकन और टिन में पेक की हुई टोमेटो प्यूरी।'*

*'तो, जमीन? बेच दी? वहाँ मकान बना लिया?' मैंने थोड़ा खीझकर पूछ लिया।*

*जवाब आया, 'खेती करते हैं।'*

*'काहे की?'*

*'सिरीक्लचर (रेशम) ...!'*

*सब कुछ विदेश में निर्यात के लिये उगाते हैं। उनसे बिना पूछे ही मैं ये हकीकत समझ गई।*

इसका नाम है 'कैश क्रोप' यानी की नकदी फसल। यदि ऐसी स्थिति है जहाँ किसान को केवल नकदी फसल ही उगानी है, तो क्या किसान परिवार नकदी पकाने से अपनी भूख मिटाएगा? नहीं, दैनंदिन खुराक, चिकन और टोमेटो दूसरे देशों से आयात करके खाते हैं। खुराक के आयात-निर्यात के प्रवास में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, यह विचारणीय है। और अंत में, *कौन इस विपदा को टाल सकता है? हमारे खुद के गाँव की जमीन, गाँव का पानी, गाँव की हवा - इसके सिवा मुझे कोई दूसरा तारणहार दिखाई नहीं देता।* ■■

# पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के चलते दृश्य कुछ ऐसा है

'सेवा' बंगाल मुख्य रूप से तीन जिलों मुर्शिदाबाद, नादिया और मालदा में कार्य कर रही है और इन तीन जिलों में हमारी 14,650 बीड़ी बनाने वाली बहनें, 4,000 बुनकर बहनें और 2,000 घरेलू कामगार बहनें सदस्य हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस के प्रभाव और परिणाम इस पृथ्वी पर लगभग सभी ने महसूस किए हैं और बंगाल के समुदाय भी इसमें शामिल हैं। इस महामारी के प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आने के साथ-साथ हमारी सदस्य बहनों के जीवन में आर्थिक रूप से भी बहुत परिवर्तन आया। स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आई जिसका सदस्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

हथकरघा साड़ी उद्योग में महिलाओं का काम पूरी तरह से बाधित और रूका हुआ है। इन बहनों को जो ऑर्डर्स मिले थे वे उन्होंने पूरे तो कर लिए लेकिन उसी दौरान लॉकडाउन लग जाने के कारण उनका काम उनके घर में ही पड़ा रह गया। बाज़ार बंद हो गए और इन बुनकर बहनों के लिए आय का कोई स्रोत नहीं बचा। आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से बाधित हुई। बंगाल में इस विपदा ने बुनकरों को बहुत नुकसान पहुँचाया है क्योंकि अप्रैल माह को बंगाली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर लोग आम दिनों से ज्यादा खरीदारी करते हैं और इस तरह कई उत्पाद भी खरीदे जाते हैं। लेकिन अब बाजार बंद हैं और लोग भी अपने-अपने घरों में बंद हैं। अब तक न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने इस आपदा के लिए किसी विशेष समर्थन या आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। कई परिवार नि:शुल्क राशन वितरण का लाभ उठा नहीं पाए यहाँ तक कि आरएसबीवाई कार्ड वाले भी परेशान हो रहे हैं।

बीड़ी कामगार और उनके परिवारों को लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। बाज़ार बंद हो गए हैं इसलिए बीड़ी की बिक्री और बीड़ी का व्यापार दोनों रूक गए हैं। चावल और गेहूँ के रूप में मिलने वाला मुफ्त राशन पूरे परिवारों का पेट भरने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है।

महिला घरखाता कामगारों की स्थिति बहुत विकट है। आय का कोई स्रोत नहीं, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं और सरकारी सहायता के कार्यक्रम भी सीमित हैं। इसके परिणामस्वरूप ये घरखाता कामगार आय और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर कोविड-19 के दुष्परिणामों को झेल रहे हैं।

लॉकडाउन के कारण इन घरेलू कामगारों को अप्रैल महीने में कोई आय नहीं हुई। इस महामारी ने इन घरखाता कामगारों के नियोक्ताओं को भी प्रभावित किया है इसलिए कई कामगारों को काम से हटा दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये परिवार लॉकडाउन के दौरान घरेलू कामगारों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अपने सदस्यों को मदद करने की दृष्टि से 'सेवा' ने राशन और स्वास्थ्यकिट उपलब्ध करवाईं हैं ताकि इस कठिन समय में वे अपने पोषण और स्वास्थ्य का जतन कर पाएँ। ***घरेलू कामगार अबीरा कहती है कि 'इस किट की मदद से हमारे 15 दिन आराम से निकल जाएँगे।'***

'सेवा' की जड़ें बंगाल के समुदाय में बहुत गहराई तक पैठी हैं। 'सेवा' स्थानीय आगेवान बहनों के मार्फत अपनी सदस्य बहनों तक सूचना, जागरूकता, परामर्श और

सरकारी सेवा से लाभ कैसे उठाया जाए–ये सारी सुविधाएँ पहुँचाती है। हम समुदायों तक निम्नलिखित तरीकों से मदद पहुँचा रहे हैं:

❖ अपनी सदस्य बहनों को आवश्यक राशन वितरण, नकद हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ना। यहाँ अभी बेरोज़गारी और आय–हानि की दर काफी अधिक है। 'सेवा' बंगाल अपनी सदस्यों को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ती है ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

❖ महिलाओं ने आजीविका विकल्प के रूप में मास्क बनाना शुरू कर दिया है और मास्क के लिए कपड़ा प्राप्त करने के लिए उन्हें पंचायत के साथ जोड़ा जा रहा है। मास्क और पीपीई किट की वर्तमान में अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकार और स्थानीय स्तर पर भी काफी जरूरत महसूस की जा रही है। इसी के मद्देनज़र 'सेवा' बंगाल अपनी सदस्य बहनों को आजीविका सुलभ कराने के लिए मास्क के उत्पादन में मदद कर रही है।

❖ गलत अफवाहों से निपटने के लिए हम अपनी स्थानीय आगेवान बहनों और युवा समूहों को पैम्फलेट्स, वॉयस मैसेज और सीधे फोन करके भी जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर कोविड–19 और इसके उपचार को लेकर कई तरह की भ्रामक और गलत सूचनाएँ प्रसारित की जा रही हैं। 'सेवा' बंगाल अपने आगेवानों और युवाओं द्वारा समुदायों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुँचाने का काम कर रही है।

❖ समुदाय के सदस्यों को उनकी स्थिति के आधार पर राशन और स्वास्थ्य किट वितरित करना शुरू किया। यहाँ कई परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में भी असमर्थ साबित हो रहे हैं। कोविड–19 ने कमजोर को और भी ज़्यादा कमजोर बना दिया है। 'सेवा' बंगाल ने सबसे अधिक जरूरत वाले लोगों को राशन किट के वितरण में सहायता की है।

❖ 'सेवा' बंगाल ने राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लाभ–राशि में वृद्धि के लिए राज्य सरकार को सीधी/संयुक्त याचिका भी दायर की है। 'सेवा' बंगाल का मानना है कि व्यवस्थित बदलाव के लिए सरकार के साथ समन्वय महत्त्वपूर्ण है।

❖ 'सेवा' इस बात को सुनिश्चित करती है कि पीडीएफ दुकानों से शासन द्वारा दिए जाने वाले राशन का वितरण समुदाय में ठीक तरह से हो सके। इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि इस प्रणाली के ठीक तरह से काम न कर पाने की जानकारी भी सरकार तक पहुँचाई जा सके।

बीड़ी कामगार और उनके परिवारों को लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बीड़ी का व्यापार और बिक्री पूरी तरह से रुक गए हैं। इसके अलावा, अधिकांश परिवारों में एक या अधिक परिवार के सदस्य दूसरे शहरों में प्रवासी श्रमिक के तौर पर गए हुए हैं जो वापस नहीं आ पाए। ये प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के लिए आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण इनमें

से कई की नौकरियाँ चली गईं और कई अभी भी दूसरे राज्य में फँसे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि बीड़ी बनाने का काम जारी रखा जा सकता है बशर्ते कि वह घर में बैठकर किया जाए न किसी महिलाओं के समूह द्वारा। इस छूट के बावजूद इन परिवारों के लिए स्थिति अभी भी कठिन है क्योंकि अधिकांश लोग कच्चा माल प्राप्त करने में असमर्थ हैं और राज्य की सीमाओं पर बीड़ी नहीं बेची जा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला के टूटने और बाहर से पैसा न आ पाने की स्थिति में इन परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा है।

कंपनियों को कच्चा माल और बीड़ी राज्य की सीमापार ले जाने के लिए सरकार से परिवहन अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

इसी तरह की स्थिति बुनकरों की भी है। उनको भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे भी अपनी रोज़गार संबधित वस्तुओं को खरीदने या अपने उत्पादों को बेचने में असमर्थ हैं। इन घरखाता कामगारों को भी परिवहन के लिए परमिट की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल में, लोगों को राशन के रूप में केवल चावल और गेहूँ मिल रहा है। यदि दाल, आलू, और नमक जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों को भी दिये जाने वाले राशन में शामिल कर लिया जाए तो जरूरतमंद लोगों को आवश्यक कैलोरीयुक्त और पोषक भोजन मिल पाएगा। इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

**– सुश्री मोमिता,**
**स्टेट को-ऑर्डिनेटर**

## इस महामारी से बचने के लिए क्या करें, क्या न करें।

1. आगामी 2 वर्षों के लिए विदेश प्रवास बंद।
2. आगामी 1 वर्ष के लिए बाहर का खाना बंद।
3. विवाह समारोह, अन्य आयोजनों में बहुत आवश्यक न हो तो न जाएँ।
4. गैर-जरूरी प्रवास बंद।
5. कम से कम एक वर्ष तक घनी बस्ती वाले क्षेत्रों में न जाएँ।
6. 'सामाजिक दूरी' का पूर्णत: पालन करें।
7. जिन्हें कफ की समस्या हो उनसे दूर रहें।
8. चेहरे पर मास्क पहने रहें।
9. आपके आसपास लोगों की भीड़ न हो, इसका ध्यान रखें।
10. शाकाहारी खुराक लेना बहुत अच्छा है।
11. सिनेमा, थिएटर, मॉल, भीड़भाड़ वाले बाज़ारों में जाना आगामी छह माह तक बिलकुल बंद रखें।
12. रोग प्रतिकारक (इम्युनिटी) शक्ति में बढ़ोतरी करें।
13. गैर-जरूरी बैठकों से दूर रहें।
14. नाई की दुकान या ब्यूटीपार्लर में जाएँ तो कड़ी निगरानी रखें।
15. कोरोना की विपदा झट से जाने वाली नहीं है।
16. कपड़े पहनते समय बेल्ट, अँगूठी, हाथ की घड़ी जैसा कुछ न पहनें। घड़ी की जरूरत भी क्या है? आपके मोबाइल में भी तो समय दिखता है।
17. रूमाल न रखें, सेनिटाइज़र या टिश्यु का उपयोग करें।
18. जूते-चप्पल घर के भीतर ना लायें, बाहर रखें।
19. बाहर से घर आयें तो हाथ-पैर को अच्छी तरह से धोएँ।
20. किसी बीमार के पास जाना पड़े तो घर आकर तुरंत सिर से पाँव तक स्नान करें।

लॉकडाउन हो ना हो, आने वाले 6 से 12 महीने अतिरिक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है। परिजन, रिश्तेदार, मित्र आदि सभी को बतायें। यह सूचना ***इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दिल्ली*** की ओर से तमाम देशवासियों को दी गई है।

'सेवा' की बहनें इसका पालन करेंगी, खुद के लिए भी और विश्व के सभी लोगों के लिए भी।

***'हम सब एक हैं!'***

## श्रमजीवी बहनों की वित्तमंत्रीजी से भावपूर्ण निवेदन

माननीयश्री, निर्मला सीतारमणजी,

हम केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना से खड़ी हुई आपदा से निपटने के लिये उठाए गए कदम के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 93.7% कामगार सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ गरीब, असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जैसे कि कॉण्ट्रेक्ट पर काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले, निर्माण कामगार, खेत मजदूर, घरखाता कामगार या जो टेक्सटाइल और गारमेन्ट उद्योग से जुड़े हैं, बीड़ी कामगार, स्वरोजगार करने वाले जैसे कि बिक्रीकर्ता/फेरीवाले, वेस्ट रिसाईकलर्स, हाथगाड़ी खींचने वाले, रिक्शा चालक और कई अन्य तरीके से अपनी दैनंदिन जरूरतें पूरी करने हेतु इन्हें रोज-रोज संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना वायरस के कारण उनकी रोज की कमाई पर बड़ी मार पड़ी है और वे अपने आपको टिकाये रखें, ये एक बड़ा संघर्ष है, जिसके कुछ उदाहरण देखें तो ...

'स्वच्छ भारत अभियान' के सच्चे योद्धा तो वेस्ट रिसाईकलर्स हैं लेकिन इस परिस्थिति में उन्हें पर्याप्त मात्रा में वेस्ट नहीं मिलता और जो थोड़ा-बहुत मिलता है उसे पीठेवाले को बेचने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि पीठेवाले ने अपना पीठा/गोदाम बंद कर दिया है। इसके अलावा, घरबैठे कपड़े पर कढ़ाई काम करने और उस पर जरी व स्टोन लगानेवाले करोड़ों कामगार हैं। इनमें से एक बड़े हिस्से के कामगारों को उनका काम बड़ी दुकानों और विदेश से मिलने वाले ऑर्डर द्वारा मिलता है जो हाल की स्थिति में पूर्णतया बंद है। मिसाल के तौर पर लखनऊ के चार लाख चिकन एम्ब्रोइडरी करने वाले कामगारों का काम बंद है क्योंकि वे हाथ से कपड़े पर कढ़ाई करते हैं और इन हाथों से होने वाले काम से वायरस फैलने के डर के चलते उनकी रोजी भी पूरी तरह बंद है। किसानों की हालत भी विषम है क्योंकि उनकी उपज भी फिलहाल व्यापारी नहीं खरीद रहे हैं। इसमें भी सब्जी-भाजी उगाने वाले किसानों की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि उनकी उपज लंबे समय तक रखी नहीं जा सकती है और खराब हो जाती है इसलिए उन्हें बहुत कम कीमत पर उसे बेचना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में काम करने वाले घरेलू कामगारों को इस लॉकडाउन के कारण कोई घर में काम के लिये आने नहीं देता इसलिए उनकी भी रोजी बंद हो गई है और कोई आवक भी नहीं है। निर्माण काम उद्योग पूरी तरह से ठप्प हो जाने के कारण उससे जुड़े लाखों निर्माण कामगार बेरोज़गार हो गये हैं। बिक्रीकर्ताओं के स्वाभाविक बाजार बंद होने से लाखों बिक्रीकर्ता/फेरीवालों की हालत भी कठिन हो गई है। रिक्शाचालकों को कोई पैसेंजर नहीं मिलने से उनकी आय भी ठप्प हो गई है। हजारों की संख्या में अनेक कामगार जो शहरों में काम करते थे, वे अब अपने गाँव की ओर वापस जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ रही हैं।

इतने जोखिम को भोगने पर भी कुछ असंगठित क्षेत्र के कामगार मूलभूत जरूरतों, सेवाओं को पूरी करने का काम कर रहे हैं। इनमें ताजा फल और सब्जी-भाजी की आपूर्ति करने वाले बिक्रीकर्ता/फेरीवाले, देश के लिए जरूरी अनाज उगाने वाले खेत मजदूर, जीवन के लिए आवश्यक सामान और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले ट्रक ड्राइवर, रिक्शाचालक और अन्य ट्रांसपोर्टर, वातावरण को सम्हालने वाले वेस्ट रिसाइकलर्स और सफाई कामगार, आवश्यक दवाई और मास्क लोगों को मिलते रहें, इसके लिए उसका उत्पादन करने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले और बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी के कॉण्ट्रेक्ट कामगार आदि समाहित हैं।

इस परिस्थिति में 'सेवा सेना' देश के 18 राज्यों की 17 लाख स्त्री कामगार सदस्यों की ओर से सरकार से निम्नलिखित आवश्यकताओं की घोषणा करने के लिए अपील करते हैं:

1. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के परिवार इस कठिन समय में अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा

कर सकें और इस स्थिति के सामने टिक सकें, इसके लिए उन्हें इन्कम सपोर्ट मिले।

2. तमाम राज्यों के मकान और अन्य निर्माण कामगार वेलफेयर बोर्ड तथा राज्यों के अन्य वेलफेयर बोर्ड में दर्ज़ प्रत्येक कामगार को हर माह 5,000 रुपये मिलें, सरकार द्वारा इसका निर्देश दिया जाये।

3. इस कठिन समय का अंत ना आये तब तक सस्ते अनाज की दुकानों के द्वारा नि:शुल्क राशन दिया जाये।

4. तमाम लोन को चुकाने के लिए 6 महीने की मुक्ति मर्यादा।

**मनाली शाह**
**नेशनल सेक्रेटरी 'सेवा'**

**ज्योति मेकवान**
**प्रधानमंत्री, 'सेवा'**

○

## अपील

### वित्तमंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से

हम आपके द्वारा हाल में गरीब श्रमजीवी वर्ग को कोविड-19 की कठिनाई से निकालने के लिए उठाये गये आर्थिक कदमों का स्वागत करते हैं, परंतु असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रमजीवी बहनों के साथ एक केन्द्रीय युनियन के तौर पर 47 वर्षों के काम के अपने अनुभव पर कुछ सुझाव हम नीचे लिखे मुताबिक देना चाहते हैं:

1 आपने मकान और निर्माणकाम कामगार वेलफेयर बोर्ड को 31,000 करोड़ रूपये 3.5 करोड़ निर्माण कामगारों के हित में उपयोग के लिए निर्देश दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी विनती है कि प्रत्येक राज्य के निर्माणकाम और कामगार वेलफेयर बोर्ड में से 5,000 रुपये प्रत्येक कामगार को मिलें, इसके लिए आप निर्देश दें। जिससे राज्य स्तर पर तात्कालिकता का एहसास हो।

2 दूसरे यह कि, जितने निर्माणकाम कामगारों का पंजीयन राज्य मकान और निर्माणकाम कामगार वेलफेयर बोर्ड में हुआ है उनमें से प्रत्येक को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए तथा जिन कामगारों के पंजीयन का रिन्यूअल किसी कारणवश नहीं हुआ है उन कामगारों को भी आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए अन्यथा इस कठिन समय में गरीब कामगारों के साथ अन्याय होगा।

3 आपने मनरेगा के तहत काम करने वाले कामगारों के वेतन में बढ़ोतरी की है लेकिन फिलहाल लॉकडाउन और सामाजिक अंतर के कारण ये कामगार काम पर नहीं जा सकते हैं। इस स्थिति में मनरेगा के तहत दर्ज़ हुए तमाम कामगारों को 5,000 रुपये उनके बैंक खाते में जमा हों, इसके लिए हम अपील करते हैं।

4 सरकार द्वारा कर्ज की अदायगी के लिए 3 माह की मुक्ति दी गई है, यह स्वागतयोग्य है लेकिन कामगारों की टूटी हुई आर्थिक परिस्थिति देखते हुए यह समयमर्यादा 6 माह की करनी चाहिए।

हमारी विनती है कि गरीब, रोज़ कमाकर रोज़ खानेवाले श्रमजीवी कामगार कोविड-19 की इस विपदा का सामना कर सकें, इसके लिए हमारे सुझावों को ध्यान में लेंगे।

आभार सहित,

**मनाली शाह**
**नेशनल सेक्रेटरी 'सेवा'**

**ज्योति मेकवान**
**प्रधानमंत्री, 'सेवा'**

# सेवा उत्तरप्रदेश द्वारा घरखाता कामगारों के लिए माँगपत्र

*कोविड-19 के कारण उत्तरप्रदेश के लाखों चिकन, ज़रदोज़ी तथा होम बेस्ड वर्कर्स के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन होने के कारण ठेकेदार द्वारा दिया गया काम कामगारों के पास ही रह गया जिसके कारण उनको काम की मजदूरी नहीं मिल पाई है। काम अधूरा है। रॉ-मटेरियल नहीं है। व्यवसाय का यह पीक सीजन है। काफी माल अंतराष्ट्रीय बाज़ार में जाता है तथा काफी उत्पाद पर्यटक खरीदते हैं। व्यवसायियों के अनुसार कम से कम एक से डेढ़ वर्ष लगेगा सामान्य स्थिति आने में। नये काम के लिए सीजन समाप्त हो जाएगा। लाखों कामगार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद इनकी समस्याएँ बढ़ जाएँगी। 'सेवा' एक केन्द्रीय यूनियन है अतः होम बेस्ड वर्कर विशेष तौर पर चिकन-ज़रदोज़ी कारीगरों के लिए निम्नलिखित माँग करता है:*

1. *होम बेस्ड वर्कर्स के लिए सरकार अन्य व्यवसाय की भांति तुरन्त राहत की घोषणा करे।*
2. *सरकार GST को चिकन, ज़रदोज़ी तथा अन्य होम बेस्ड उत्पादन पर कम से कम 3 वर्ष के लिए रोक लगाये।*
3. *कपडा मंत्रालय द्वारा जारी किये जा रहे आर्टिसन कार्ड को मान्यता मिले इसको सामाजिक सुरक्षा कवर तथा सरकार के द्वारा की गई राहत घोषणाओं से लिंक किया जाये।*
4. *ये भ्रान्ति ख़तम की जाये कि कपड़ों पर कोरोना वायरस अधिक समय तक जीवित रहता है; इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर हो रहा है।*
5. *सरकार द्वारा होम बेस्ड वर्कर के लिए रिहैबिलिटेशन पैकेज घोषित किया जाये।*
6. *कोविड-19 के कारण संकट में आये चिकन और अन्य होम बेस्ड कार्य को बचाने के लिए सरकार उचित कदम उठाये।*
7. *चिकन उद्यमी तथा अन्य होम बेस्ड उद्यमी द्वारा बैंक से लिए गए कर्ज की कर्ज माफी की जाये।*
8. *चिकन ज़रदोज़ी आर्टिसन बहनों के लिए नीति का निर्माण किया जाये।*
9. *होम बेस्ड वर्कर द्वारा बनाए जा रहे मास्क पर जीएसटी समाप्त किया जाये।*

*फरीदा जलीस*
*महामंत्री सेवा उत्तरप्रदेश*

*( यह पत्र ट्रेड यूनियन ज्वाइंट मोर्चा के लेटर हेड पर उत्तरप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की मांग कर रहे हैं।)*

# हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचाई

कोरोना वायरस की विपदा आने के पूर्व 'सेवा' दिल्ली की टीम दंगा पीड़ितों को राहत पहुँचाने में लगी हुई थी। कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने लोगों को अभी राहत सामग्री मिली है या नहीं मिली आदि को लेकर रणनीति बना रही थी। ये दंगा पीड़ित लोग अभी इस सदमे से उबर ही रहे थे कि कोरोना वायरस की विपदा आ पड़ी।

अब टीम के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस से अपने सदस्यों को बचाने की थी। उसके बाद ही प्रधानमंत्रीजी ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हमें यह समझ में आ गया था कि इसके चलते सबसे बुरी हालत दिहाड़ी मजदूरों की होने वाली थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 'सेवा' संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने उसी समय एक दिन का वेतन लोगों को राशन पहुँचाने के लिए दिया ताकि जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुँचाया जा सके।

दिल्ली सरकार के साथ 'सेवा' के बेहतरीन तालमेल के चलते सरकार ने जो राशन कमेटी बनाई उसमें 'सेवा' को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब 'सेवा' की टीम को अपने सदस्यों के साथ-साथ दिल्ली के सभी क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों

*मेरा नाम भागवती है। मैं सुंदरनगरी में रहती हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मैं, मेरे पति, तीन बच्चे और मेरी सासुमाँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ। आस-पड़ोस की महिलाओं के ब्लाउज़ सिलकर देती हूँ और जो मिलता है उसी से मेरे परिवार की गुजर-बसर चलती है। मेरे पति पहले फैक्ट्री में काम करने जाते थे लेकिन पिछले 5 वर्षों से उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है इसलिए अब बाहर जाकर काम नहीं कर पाते हैं और सिलाई काम में मेरी मदद करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय लगभग 10-20 दिन का सिलाई का काम मेरे पास था। फिर धीरे-धीरे महिलाओं ने सिलाई देना बंद कर दिया क्योंकि लॉकडाउन में सभी कुछ बंद हो गया। मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए मैं एक दिन सेवा सेंटर सुंदर नगरी गई। वहाँ पर राशन बाँटने की तैयारी चल रही थी। मैंने लताबेन से कहा कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ रहकर सेवा का काम करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ दो अन्य बहनों के साथ रात में रूक सकते हो? इसके एवज में आपको 300 रुपये मिलेंगे। मैंने खुशी से हाँ कह दिया क्योंकि इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। वहाँ बहुत सारा राशन था। दिन में सेंटर की साफ- सफाई करना और राशन की पेकिंग में सहयोग करना मेरा काम था। इसके लिए मुझे सेवा से 2000 रुपये मेहनताने के रूप में दिए गए। ये पैसे मुझे उस समय मिले जब मेरे घर में आटा व चावल तो था लेकिन घर का अन्य समान जेसे तेल, चीनी, मसाले, दाल आदि खत्म हो गये थे। पैसे मिलते ही मैं सबसे पहले किराने की दुकान पर गई और उन पैसों से जरूरी राशन भरवाया। सेवा सेंटर से राशन की पूरी किट दी जा रही लेकिन लेकिन वह सिर्फ उनके लिये थी जिनका राशन कार्ड नहीं है लेकिन मेरा राशन कार्ड है इसलिये मैंने वो किट नहीं ली। राशन का काम समाप्त हुआ तो अब सेवा सेंटर में मास्क बनने का काम भी आने लगा है इसलिए अब मैंने मास्क बनाने भी शुरू कर दिये हैं। कहते हैं न कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मुझे खुशी हो रही है कि जब चारों तक चेहरों पर निराशा छाई हुई है ऐसे समय में सेवा ने आगे बढ़कर सभी की मदद की और उनकी निराशा को दूर किया।*

तक राशन की किट तैयार करके पहुँचानी थी।

दिल्ली सरकार ने सुंदर नगरी स्थित 'सेवा' सेंटर को राशन केन्द्र बनाया जहाँ से पूरी दिल्ली में राशन सप्लाई किया जाना था। इस काम में हमारे आगेवानों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और पूरी दिल्ली के कोने-कोने तक ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुँचाया। 'सेवा' ने न सिर्फ सरकार की मदद से राशन वितरण किया बल्कि अन्य संस्थाओं से भी मदद का निवेदन किया और राशनकिट प्राप्त करके जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाई।

राशन वितरण में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि हर जरूरतमंद तक राशन पहुँचे फिर भले ही उसके पास राशन कार्ड हो अथवा न हो। ऐसे श्रमजीवियों की लिस्ट तैयार की गई जो किराये से रहते थे और जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन आधार कार्ड थे। 'सेवा' जिन क्षेत्रों में कार्यरत है वहाँ पर लगभग 3,500 परिवार को राशन दिया गया। इस प्रकार हर गरीब, प्रवासी श्रमजीवी तक राशन पहुँचा।

राशन बाँटते समय यह समझ में आया कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं

लेकिन आधार कार्ड हैं। सरकारी राशन का वितरण राशन कार्ड के आधार पर होना था। अब मुश्किल यह थी कि ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन तक सरकारी राशन कैसे पहुँचाया जाए। तब 'सेवा' की ओर से दिए गए सुझाव के आधार पर अस्थाई राशन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें उन लोगों का पंजीयन किया गया, जिनके पास केवल आधार कार्ड ही था। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम है और वह अपने आधार को अस्थाई राशन कार्ड से जुड़वाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है और ऑनलाइन प्रक्रिया में ही पता चल जाता है कि यह व्यक्ति पहले से राशनकार्ड धारक है। हालांकि इस प्रक्रिया को समझने में लोगों को लगभग 15 दिन लगे लेकिन आखिरकार सभी लोगों को यह समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एक ही पते से परिवार के आधार कार्ड व एक फैमिली फोटो डालना है। फिर क्या था इस प्रक्रिया का लोगों ने बहुत फायदा उठाया। जो लोग किन्हीं वजहों से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे उनकी 'सेवा' जैसी संस्थाओं ने मदद की। इस प्रक्रिया को करने में दो से तीन दिन का समय लगता है। उसके बाद एक रसीद दी जाती है जिसमें मुखिया का नाम, घर के सदस्यों संख्या और किस जगह से राशन प्राप्त किया जाना है, उसका पूरा पता अंकित होता है। इस रसीद अथवा कुपन को लेकर परिवार का कोई भी एक सदस्य नियत स्थान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकता है।

**-लता,**
**उपाध्यक्ष-सेवा दिल्ली यूनियन**

# सामान्य जीवन पटरी पर कब आएगा?

कोरोना वायरस ने चीन से शुरू होकर पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे विश्व में इसके कारण त्राही-त्राही मची हुई है। इस बीमारी से संक्रमित होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जिसमें से कुछ मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं लेकिन कोरोना के कारण अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।

भारत में इस बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की। इस लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र के कामगार बहनों एवं भाईयों के रोजगार पर काफी असर पड़ा है। कई लोगों का रोज़गार टूट गया। जो लोग हर दिन कमाकर खाने वाले थे उनके घरों में फाके होने लगे। दो वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल होने लगा।

हालांकि इस समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारे नियम बनाये हैं जिससे कोई भूखा न रहे। इसके अलावा देश के अमीर वर्ग को लोगों की सहायता के लिये आगे आने को कहा गया है और प्रधान मंत्री कोरोना फंड भी बनाया गया है जिसमें समर्थ लोग दान कर सकें और उस राशि का उपयोग लोगों की बेहतरी के लिए किया जा सके। कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सके तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाई जा सकें।

इस लॉकडाउन में मैं भी फंस कर रह गई। मैं अपने पति के स्वास्थ्य संबंधित टेस्ट के लिये मुम्बई आई हुई थी। सभी टेस्ट होने में एक सवा महीने का समय लग गया

और जब मेरी वापसी का समय आया तो लॉकडाउन हो गया। ट्रेनें चलना बंद हो गईं। मैं इस लॉकडाउन की मार पिछले 22 मार्च झेल रही हूँ। न कहीं जा पाती हूँ और न ही कहीं से कोई मदद ही मिल पा रही है।

मैंने यहीं से अपने कार्यालय में लोगों से बात करना शुरू किया और जिन लोगों की जो मदद कर सकती थी, वो करने लगी। मैंने अपने क्षेत्र की घरेलू कामगार बहनों से बात करके उन्हें सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया तथा सुविधा दिलवाने की कोशिश भी की।

पिछले दिनों उज्जवला योजना के तहत सरकार तीन सिलेण्डर मुफ्त दे रही है, इस बात का पता चलते ही मैंने यहीं से एच.पी. गैस गोदाम में बात की और विस्तार से जानकारी पाकर अपने कार्यालय की बहनों को बताया और इस तरह बहनों को इस योजना का लाभ मिल पाया।

बिहार में जिनके पास राशन कार्ड हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। मैंने बहनों से फोन करके पूछा तो जिनके पास कार्ड है प्राय: उन सभी को अनाज मिल गया। लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है उन्होंने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने वार्ड कमिश्नर से बात की और उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिनों में आपकी बहनों का राशन कार्ड बन जायेगा।

उसके बाद मैंने बहनों को बताया कि 'सेवा' के द्वारा घरेलू कामगार बहनों के लिये एक प्रेस विज्ञप्ति अखबार में दी गई है जिसमें 'सेवा' ने मालिकों से अपील की है कि कामगार बहनों के पैसे न काटे जाएँ और उन्हें यथासंभव मदद करें। आप सभी बहनें अपने-अपने मालिकों से अपना वेतन लेने की बात करें और कोई समस्या होने पर मुझे फोन करें।

मैंने जिन बहनों का जीरो बैलेंस पर बचत खाता

खुलवाया था उन सभी के खाते में 500 रुपये आए हैं और राशन कार्ड द्वारा भी बैंक खाते में 1000 रुपये आने की बात सुन रही हूँ। इस प्रकार कुछ-कुछ फायदे तो बहनों को मिल रहे हैं। लेकिन पता नहीं इस वायरस का अंत कब होगा तथा सामान्य जीवन पटरी पर कब आएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

बाबी बेन पति विजय राय घरेलू कामगार हैं और हमारी आगेवान भी। उन्हें राशन कार्ड के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिला इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिली। उनके घर में पैसों की बहुत तंगी है।

छोटी दौलतपुरा की रहने वाली माला बेन पति शंकर सोनी, घरेलू कामगार और आगेवान हैं। उन्हें भी राशन कार्ड के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिला। घर के सभी कमाऊ सदस्य घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

किरन देवी पति सुरेन्द्र को सरकार की तरफ से जन

**'सेवा' एक संगठन तो है ही और साथ ही आंदोलन भी है। किसी भी आंदोलन के पीछे विचार की शक्ति होती है। 'सेवा' को इलाबहन जैसी हमारे समय की प्रमुख स्त्री-चिंतक की विचार शक्ति प्राप्त है। किसी भी संगठन या आंदोलन में उसके मुखपत्र की बड़ी भूमिका होती है और यही भूमिका 'अनसूया' लगातार निभाता आ रहा है।**

धन खाता के तहत 500 रुपये आए। उनकी बेटी को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर नि:शुल्क मिला।

रीना देवी पति वाल्मीकिमंडल उम्र 35 वर्ष तल्लूपोखर नागलोक वार्ड में रहती हैं। राशन कार्ड के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिला। 500 रुपये जन धन योजना के खाते में आए और मुफ्त में गैस सिलेण्डर मिला।

ये सभी लोग अपना काम-धंधा-रोज़गार गंवाकर घर में बैठे हैं और किसी तरह अपना गुजारा चला रहे हैं। जितनी जमा पूँजी थी उसका भी उपयोग कर लिया गया है। अब तो बस वे सबकुछ ठीक होने की राह देख रहे हैं।

– **अनीता बेन**
**ऑर्गनाइज़र**

**मालिक : ''अनसूया ट्रस्ट'' की ओर से प्रकाशक-मुद्रक : प्रीति शान्त, म.प्र.हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पी.एण्ड टी. चौराहा, शास्त्रीनगर, भोपाल (म.प्र.)-462003. फोन : 0755-2790039**
**मुद्रण : प्रियंका ऑफसेट, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल. फोन : 2555789**

***अनसूया***

***अनसूया कार्यालय :***

*द्वारा- म.प्र.हिन्दी साहित्य सम्मेलन,*
*मायाराम सुरजन स्मृति भवन,पी.एण्ड टी.चौराहा,*
*शास्त्रीनगर, भोपाल (म.प्र.) 462003 फोन नं. : 2790039*

ई-मेल - **ansuya_trust@rediffmail.com,**
**website:www.sewabharat.org**